

## आपराधिक मामलों में बरी हुए व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियाँ

### प्रलिस के लिये:

[भारत-तबिबत सीमा पुलिस \(ITBP\)](#), [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम \(POCSO\)](#), 2012, [नैतिक अधमता](#), [भारतीय दंड संहिता, 1860](#), [केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल \(CAPF\)](#),

### मेन्स के लिये:

नैतिक अधमता और रोज़गार नरिण्यों पर इसके प्रभाव से जुड़े मामलों में दोषमुक्तिपर वचिार ।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र को नरिदेश दिया कि वह [भारत-तबिबत सीमा पुलिस \(ITBP\)](#) में कांस्टेबल के रूप में हरियाणा के एक व्यक्तिकी नयुक्तिपर पुनर्वचिार करे, क्योंकि उसे [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम \(POCSO\)](#), 2012 के तहत वर्ष 2019 के मामले में बरी कर दिया गया था ।

- गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) द्वारा जारी आदेश ने नैतिक अधमता के आधार पर व्यक्तिकी नयुक्तिरिद कर दी ।

## नैतिक अधमता क्या है?

- "नैतिक अधमता (moral turpitude)" शब्द, जैसा कि पी. मोहनसुंदरम बनाम राष्ट्रपति, 2013 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, में एक वशिषिट परभाषा का अभाव है ।
- इसमें न्याय, ईमानदारी, शील या अच्छी नैतिकता के वपिरीत कार्य शामिल हैं, जो ऐसे आचरण के आरोपी व्यक्तिके भ्रष्ट और दुष्ट चरतिर या स्वभाव का सुझाव देते हैं ।

## क्या है मामला?

- वर्ष 2022 में अनुकंपा के आधार पर नयुक्ति कांस्टेबल को प्रवेशन यौन उत्पीड़न से संबंधित [POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत वर्ष 2018 के आपराधिक मामले में बरी होने का खुलासा करने के बाद अपनी नयुक्तिरिद करने का सामना करना पड़ा ।](#)
- इसके अलावा, उन्हें [भारतीय दंड संहिता \(IPC\), 1860](#) की कई धाराओं के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा, जिनमें ज़हर, अपहरण और आपराधिक संबंधी धमकी से नुकसान पहुँचाने से संबंधित अपराध शामिल थे ।
- वर्ष 2019 में कैथल कोर्ट (हरियाणा) द्वारा सभी आरोपों से बरी किये जाने के बावजूद, उन्हें अपनी नयुक्तिरिद करने का सामना करना पड़ा ।
  - यह कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा [केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों \(CAPF\)](#) में नयुक्तियों के लिये जारी एक नीतिके अनुसार की गई थी, जो उन व्यक्तियों के लिये की गई थी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वे परीक्षण के अधीन हैं या पूछताछ के अधीन हैं ।
  - आपराधिक मामले में गंभीर आरोपों या नैतिक अधमता का सामना करने वाले व्यक्तियों को, भले ही बाद में संदेह के लाभ या गवाह को डराने-धमकाने के कारण बरी कर दिया गया हो, आम तौर पर CAPF में नयुक्ति के लिये अनुपयुक्त माना जाता है ।

लोक सेवा में आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों की नयुक्ति हेतु न्यायालय ने क्या आदेश नरिधारति किये हैं?

- अवतार सहि बनाम भारत संघ, 2016 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक आपराधिक मामले में शामिल उम्मीदवार की न्युक्ता पर वचिार कयिा ।
  - इसने नरिणय सुनाया ककि सिी उम्मीदवार की सज़ा, दोषमुक्ता, गरिफ्तारी या लंबति आपराधिक मामले के बारे में नयिोक्ता को दी गई जानकारी सच होनी चाहयिे और बनिा कसिी दमन या गलत जानकारी के होनी चाहयिे ।
  - ऐसे मामलों में दोषसदिधि के लयिे जो मामूली नहीं हैं, नयिोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है या उसकी सेवाएँ समाप्त कर सकता है ।
- यदकि कोई बरी नैतिकि अधमता या तकनीकी आधार पर गंभीर अपराध से जुडे मामले में हुआ है और यह स्पष्ट बरी नहीं है या उचति संदेह पर आधारति है, तो नयिोक्ता व्यक्ता की पृष्ठभूमि के बारे में सभी प्रासंगकि जानकारी का आकलन कर सकता है तथा कर्मचारी की सेवा-नरितरता के संबंध में उचति नरिणय ले सकता है ।
- सर्वोच्च न्यायालय में सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ, 2023 मामला "आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार स्वचालति रूप से पद पर नयिुक्ता का हकदार नहीं होगा" और यह अभी भी नयिोक्ता के लयिे उनके पूर्ववृत्त पर वचिार करने तथा उम्मीदवार के रूप में उनकी उपयुक्ताता की जाँच करने हेतु खुला रहेगा ।

## यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधनियिम, 2012 क्या है?

- परचिय:
  - **POCSO अधनियिम 14 नवंबर, 2012** को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परणामस्वरूप अधनियिमति कयिा गया था ।
  - इस वशिष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन शोषण के अपराधों को संबोधति करना है, जनिहें या तो वशिष रूप से परभाषति नहीं कयिा गया था या पर्याप्त रूप से दंडति नहीं कयिा गया था ।
  - अधनियिम 18 वर्ष से कम आयु के कसिी भी व्यक्ता को बच्चे के रूप में परभाषति करता है । अधनियिम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है ।
    - अपराधयिों को रोकने और बच्चों के खलिाफ ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से, बच्चों पर यौन अपराध करने के लयिुत्तयुदंड सहति अधिकि कठोर सज़ा का प्रावधान करने हेतु वर्ष 2019 में अधनियिम की समीक्षा तथा संशोधन कयिा गया ।
    - भारत सरकार ने **POCSO नयिम, 2020** को भी अधसिूचति कर दयिा है ।
- वशिषताएँ:
  - **लगि-नषिपकष प्रकृति:**
    - अधनियिम के अनुसार लडके तथा लडकयिाँ दोनों यौन शोषण के शकिार हो सकते हैं और पीडति के लगि की परवाह कयिे बनिा ऐसा दुरव्यवहार एक अपराध है ।
      - यह इस सदधिांत के अनुरूप है कसिी भी बच्चों को यौन दुरव्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है तथा लगि के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहयिे ।
  - **मामलों की रपिोर्टगि में आसानी:**
    - न केवल व्यक्तायिों द्वारा बल्कि संस्थान भी अब नाबालगिों के साथ यौन दुरव्यवहार के मामलों की रपिोर्ट करने के लयिे पर्याप्त रूप से जागरूक हैं क्योकि रपिोर्ट न करना **POCSO अधनियिम के तहत एक वशिषिट अपराध** बना दयिा गया है । इससे बच्चों से संबंधति यौन अपराधों को छपिाना तुलनात्मक रूप से कठनि हो गया है ।

## भारत-तबिबत सीमा पुलसि बल (ITBPF) क्या है?

- भारत-तबिबत सीमा पुलसि बल (Indo-Tibetan Border Police Force- ITBPF) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक **केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बल (Central Armed Police Force)** है ।
  - ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को [भारत-चीन युद्ध](#) के दौरान की गई थी तथा यह एक सीमा सुरक्षा पुलसि बल है जो उच्च तुंगता वाले अभयानों में वशिषज्ञता रखता है ।
  - वर्तमान में **ITBP** लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक 3,488 कमी. लंबी [भारत-चीन सीमा](#) की सुरक्षा के लयिे तैनात है ।
  - बल को नक्सल वशिधी अभयानों तथा अन्य आंतरकि सुरक्षा कर्त्तव्यों के लयिे भी तैनात कयिा गया है ।